loans for housing purposes/activities in the country including Union Territory of Delhi; and

(b) if so, what is the factual position in this regard and latest directives/instructions, if any, issued for giving housing loan to individuals including the members of Group Housing Societies of Delhi on liberal terms and conditions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The loans are granted by banks and other financial institutions assigned with responsibility for making housing finance available in terms of their policy applicable to the entire country and the question of any liberal terms and conditions for beneficiaries in Delhi does not arise. Reserve Bank of India (RBI) has advised the scheduled commercial banks that 1.5 percent of their incremental deposits should be earmarked for housing finance and out of that 30 percent should be provided for direct lending. Similarly HDFC has been providing loans for the benefit of people belonging to EWS, LIG & MIG. LIC has been granting loans directly to individuals who are its policy holders for acquiring residence. A subsidiary of LIC has also been set up to provide housing loans mainly to the policy holders of LIC, as its primary objective. National Housing Bank (NHB) provides refinance to scheduled commercial banks, housing finance institutions and State level cooperative housing finance societies in respect of their housing loans to the extent they qualify under the refinance policy of that Bank.

कालेधन को नियंत्रित करने के लिए कराधान प्रणाली में संशोधन

1821. **श्री रणजीत सिंह :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या वित्त मंत्री 16 जुलाई, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 195 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि काले धन में वृद्धि होने के मुख्य कारणों में से एक कारण हमारी वर्तमान कराधान-प्रणाली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रणाली में आमूल परिवर्तन करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) अवैध धन की उत्पत्ति तथा उसके प्रचुर मात्रा में एकत्र होने के अनेक कारण हैं । तथापि, इसके संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने देश की कर प्रणाली की समीक्षा करने के निमित्त डा० राजा जे० चेल्लैया की अध्यक्षता में एक कर-सुधार समिति का गठन किया है । जब कभी भी कर-प्रणाली में परिवर्तन किए जाने की परिकल्पना की जाएगी, तब सरकार उस समय इस समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखेगी ।

Including Discipline and Honesty in Corporate Sector

1822. SHRI A. G. KULKARNI:
DR. BAPU KALDATE:
SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item in Hindu dated 15th September, 1991 captioned "Is it corporate democracy" and if so whether Government feels that there is pressing need to inculcate the discipline and honesty in the corporate sector while attempting to take over other companies.

(b) whether the practices followed in Western Countries on regulations to be observed while taking over of companies will be made applicable in this country to stop the mis-adventurous manipulative skills to take

over corporate companies; and

(c) whether any action will be taken for various mis-adventures attempted by corporate sector in the last 5 years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes, Sir. There is no denying the fact that discipline and honesty are essential in the corporate sector.

(b) Clause 40 of the Listing Agreement of Stock Exchanges contains suitable provisions for preventing clandestine take-over bids and also for ensuring transparency in the interest of the investing public.

(c) Suitable action can be considered if specific instances of this nature are brought to the notice of the Government.

1823 (Transferred to the 12th December, 1991)

10 लाख रुपये से ज्यादा कर की बकाया धनराशि

1824. डा० अबदार अहमद :
कुमारी सुशीला सिरिया :

वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों, फर्मों तथा कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं जिन पर आयकर, उत्पाद शुल्क अथवा अन्य करों की 10 लाख रुपये से ज्यादा की धनराशि बकाया है ;

(ख) उनकी ओर बकाया कुल धनराशि कितनी है तथा वह कब से है ; और

(ग) इस धनराशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) कुल 857 फर्में, 2593 कम्पनियां और 2627 अन्य करदाता हैं जिनके नाम पर 31-3-91 को 10 लाख रुपए और उससे अधिक की प्रत्यक्ष कर मांगें बकाया हैं और उन पर कुल 4891.54 करोड़ रुपए की रकम देय है ।

ऐसे कुल 990 करदाता हैं जिनके नाम पर 10 लाख रुपए से अधिक का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बकाया है और उन पर कुल 1032 करोड़ रुपए की रकम देय है। सीमा शुल्क की बाबत ऐसे करदाताओं की संख्या 77 है और उन पर 72.75 करोड़ रुपए की रकम बकाया है ।

मामलों की संख्या बहुत अधिक अर्थात् 7,000 से अधिक होने के कारण व्यक्तियों, फर्मों और कम्पनियों के नाम तथा अन्य विवरण एकत्रित कर के प्रस्तुत करने में लगने वाला समय और श्रम परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । यदि माननीय सदस्य किसी व्यक्ति फर्म और कम्पनी को विनिर्दिष्ट करते हैं तो सूचना प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(ग) यथावश्यक प्रशासनिक, कानूनी और अन्य उपाय किए जा रहे हैं ।

Show cause Notice to STC by Bombay Customs Authorities

1825. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bombay Customs authorities have issued show cause notice to the State Trading Corporation (STC) for alleged misdeclaration of glazed newsprint cargo;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether the reported amount of Rs. 6 crore duty evasion charge against S.T.C. is true and whether any reply received in this connection by the concerned authorities from S.TC.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (c) Bombay Customs have